

उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873

(1873 का अधिनियम संख्यांक 8)

[11 फरवरी, 1873]

उत्तरी भारत में सिंचाई, नौपरिवहन और जल-निकासी का विनियमन करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यतः उन समस्त राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, राज्य सरकार, लोक प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक वाहिकाओं में बहने वाले सभी नदियों और झरनों के जलों का, और स्थिर जल की सभी झीलों और अन्य प्राकृतिक संग्रहों के जलों का उपयोग और नियंत्रण करने की हकदार है, और, यतः उक्त राज्यक्षेत्रों में सिंचाई, नौपरिवहन और जल-निकास से सम्बन्धित विधि का संशोधन करना समीचीन है अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम**—यह अधिनियम उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 कहा जा सकता है;

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार [उत्तर प्रदेश और उन राज्यक्षेत्रों पर है जो एक नवम्बर, 1956 के ठीक पहले पंजाब और दिल्ली राज्यों में समाविष्ट थे] और सभी भूमियों को लागू होता है चाहे स्थायी रूप से व्यवस्थापित हों, अस्थायी रूप से व्यवस्थापित हों या राजस्व से मुक्त हों।

3* * * * *

2. **[अधिनियमों का निरसन]**—निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित।

3. **निर्वचन खण्ड**—इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो :—

(1) **“नहर”**—“नहर” के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) जल के प्रदाय या भंडारकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित सभी नहरें, वाहिकाएं और जलाशय;

(ख) ऐसी नहरों, वाहिकाओं या जलाशयों से सम्बन्धित सभी संकर्म, तटबंध, संरचनाएं, प्रदाय और अतिजल वाहिकाएं;

(ग) इस धारा के द्वितीय खण्ड में यथापरिभाषित सभी जलसरणियां;

(घ) किसी नदी, सरिता, झील या जल के प्राकृतिक संग्रह, या प्राकृतिक जल-निकास वाहिका का कोई भाग जिसको राज्य सरकार ने इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्ध लागू किए हैं;

(2) **“जलसरणी”**—“जलसरणी” से ऐसी वाहिका अभिप्रेत है जिसमें किसी नहर से पानी प्रदाय किया जाता है किन्तु जिसका अनुरक्षण राज्य सरकार के खर्चे पर नहीं किया जाता है और ऐसी वाहिका के सभी सहायक संकर्म;

(3) **“जल निकास संकर्म”**—“जल निकास संकर्म” के अन्तर्गत किसी नहर से अतिजल वाहिका, बाढ़ से या कटाव से भूमि के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या अनुरक्षित बांध, वीयर तटबंध, स्लूस, पुलनिरोध और अन्य संकर्म हैं; किन्तु इसके अन्तर्गत शहरों से मल हटाने के संकर्म नहीं हैं;

⁴(4) **“जलयान”**—“जलयान” के अन्तर्गत नौका, बेडा काष्ठ और अन्य प्लवमान वस्तुएं हैं;

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा यथासंशोधित मूल शब्दों के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित। अधिनियम मूलतः उन राज्यक्षेत्रों पर, जो अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रान्त हैं, विस्तारित किया गया। इसे मध्य प्रान्त सिंचाई अधिनियम, 1931 (1931 का मध्य प्रान्त 3) द्वारा मध्य प्रान्त में निरसित किया गया। इसके, पंजाब लघु नहर अधिनियम, 1905 (1905 का पंजाब अधिनियम सं० 3) की अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के अधीन फिलहाल सम्मिलित किसी नहर पर लागू न होने की घोषणा की गई, देखिए उस अधिनियम की धारा 2(3)। अधिनियम का संशोधन, पंजाब में 1953 के पंजाब अधिनियम सं० 19, 1960 के पंजाब अधिनियम सं० 22 और 1947 के पंजाब अधिनियम सं० 18 द्वारा; उत्तर प्रदेश में 1956 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30 और 1974 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16 द्वारा; तथा हरियाणा में 1971 के हरियाणा अधिनियम सं० 4 और 1974 के हरियाणा अधिनियम सं० 29 द्वारा किया गया।

² विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “पंजाब और दिल्ली राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा प्रारम्भिक पैरा निरसित किया गया।

⁴ साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3(3) में परिभाषा देखिए।

(5) “आयुक्त”—“आयुक्त” से खण्ड का आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी है;

¹(6) “कलक्टर”—“कलक्टर” से जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलक्टर की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त उपायुक्त या अन्य अधिकारी भी है;

(7) “नहर अधिकारी”—“नहर अधिकारी” से इस अधिनियम के अधीन किसी नहर या उसके किसी भाग पर नियंत्रण या अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

“नहर अधीक्षक अधिकारी”—“नहर अधीक्षक अधिकारी” से किसी नहर या नहर के प्रभाग पर साधारण नियंत्रण रखने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

“नहर खण्ड अधिकारी”—“नहर खण्ड अधिकारी” से नहर के किसी खण्ड पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

“नहर उपखण्ड अधिकारी”—“नहर उपखण्ड अधिकारी” से नहर के किसी उपखण्ड पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

(8) “जिला”—“जिला” से राजस्व प्रयोजनों के लिए नियत किया गया जिला अभिप्रेत है।

4. अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर वे अधिकारी घोषित कर सकती है जिनके द्वारा, और वे स्थानीय सीमाएं जिनके अन्दर, इसमें इसके पश्चात् प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा।

धारा 3 के खण्ड (7) में उपवर्णित सभी अधिकारी ऐसे अधिकारियों के आदेश के अधीन होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

भाग 2

लोक प्रयोजनों के लिए जल का उपयोजन

5. जब जलप्रदाय का लोक प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाना है, तब अधिसूचना का जारी किया जाना—जब कभी राज्य सरकार को यह समीचीन प्रतीत होता है कि किसी प्राकृतिक वाहिका में बहने वाली किसी नदी या सरिता या किसी झील या स्थिर जल के किसी अन्य प्राकृतिक संग्रह के जल का किसी विद्यमान या परियोजित नहर या जल-निकास संकर्म के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोजन या प्रयोग किया जाना चाहिए तो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि उक्त जल उक्त अधिसूचना में नियत दिन के पश्चात्, जो उस तारीख से तीन मास से पूर्व नहीं होगा, तदनुसार उपयोजित या प्रयोग किया जाएगा।

6. नहर अधिकारी की शक्तियां—इस प्रकार नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय, कोई नहर अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कार्य करते हुए, किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है और किन्हीं बाधाओं को हटा सकता है, और वाहिकाओं को बन्द कर सकता है और उक्त जल के इस प्रकार उपयोग या प्रयोग के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य कर सकता है।

7. प्रतिकर के दावों के बारे में सूचना—एसी अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से कलक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना कराएगा, जिसमें यह कथित होगा कि राज्य सरकार उक्त जलों का यथापूर्वोक्त उपयोजन या प्रयोग करना चाहती है, और धारा 8 के उपवर्णित विषयों की बाबत प्रतिकर के लिए दावे उसके समक्ष किए जा सकते हैं।

8. नुकसान जिसके लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा—निम्नलिखित से हुए किसी नुकसान के लिए कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा :—

(क) अन्तःस्रवण या बाढ़ में रोक या कमी;

(ख) जलवायु या मिट्टी का क्षय;

(ग) नौपरिवहन या काष्ठ के बहाने या जानवरों को पानी पिलाने के साधन का रोका जाना;

(घ) श्रमिकों का विस्थापन।

वे विषय जिनकी बाबत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकता है—किन्तु निम्नलिखित विषयों की बाबत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकता है :—

(ड) किसी परिनिश्चित कृत्रिम वाहिका को जो उक्त अधिसूचना की तारीख को उपयोग में है, चाहे भूमि के ऊपर हो या नीचे, किसी प्राकृतिक वाहिका के माध्यम से जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

¹ साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 देखिए।

(च) लाभ के प्रयोजन के लिए किसी जलसरणी पर, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, बनाए गए किसी संकर्म को जो उक्त अधिसूचना की तारीख को उपयोग में है जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

(छ) किसी ऐसी प्राकृतिक बाहिका के, जो उक्त अधिसूचना की तारीख के ठीक पहले पांच वर्षों के अन्दर सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग में है, माध्यम से जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

(ज) किसी जलसरणी या किसी जल प्रयोग के किसी अधिकार की बाबत, जिसका कोई व्यक्ति भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) के भाग 4 के अधीन हकदार है, किया गया नुकसान;

(झ) कोई अन्य पर्याप्त नुकसान जो ऊपर के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नहीं आता है, और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण हुआ है और जो ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत किए जाने के समय अभिनिश्चित और प्राक्कलित किया जा सकता है।

ऐसे प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में, जिस सम्पत्ति की बाबत प्रतिकर का दावा किया गया है, उसके बाजार मूल्य में, प्रतिकर अधिनिर्णीत किए जाने के समय हुई कमी को ध्यान में रखा जाएगा, और जहां ऐसा बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है वहां प्रतिकर, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक शुद्ध लाभ में हुई कमी के बराबर गुने के बराबर रकम समझा जाएगा।

ऐसे किसी संकर्म या बाहिका की बाबत जो इस अधिसूचना की तारीख को प्रयोग में नहीं है इस धारा के खण्ड (ड), (च) और (छ) में निर्दिष्ट किसी जल प्रदाय के लिए कोई अधिकार राज्य सरकार के विरुद्ध, अनुदान द्वारा या भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) के भाग 4 के अधीन या अनुदान द्वारा ही अर्जित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

और इस धारा के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट किन्हीं फायदों के लिए कोई अधिकार राज्य सरकार के विरुद्ध उसी भाग के अधीन अर्जित नहीं किया जाएगा।

9. दावों का परिसीमन—किसी रोक, कमी या नुकसान के लिए प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसे रोक, कमी या नुकसान से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जब तक कलक्टर का यह समाधान नहीं हो जाता है कि दावेदार को ऐसी कालावधि के अन्दर दावा नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

10. दावों की जांच और प्रतिकर की रकम—कलक्टर ऐसे दावों की जांच और प्रतिकर की रकम, जो दावेदार को दी जानी चाहिए, यदि कोई हो, अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 (1870 का 10) की धारा 9 से 12 (दोनों सहित), 14 और 15, 18 से 23 (दोनों सहित), 26 से 40 (दोनों सहित), 51, 57, 58 और 59 ऐसी जांच को लागू होंगे :

परन्तु उक्त धारा 26 के अन्तिम खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा : “इस धारा के और उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) की धारा 8 के उपबंध, प्रत्येक असेसर को इसके पहले कि वह अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर के बारे में अपनी राय दे, ऐसी भाषा में पढ़ कर सुनाए जाएंगे जो वह समझता है।”।

11. जल प्रदाय में अवरोध होने पर भाटक का उपशमन—अपर्यवसित पट्टे के अधीन धारण करने वाला या अधिभोग का अधिकार रखने वाला प्रत्येक अभिधारी, जो उस समय किसी भूमि के अधिभोग में है जब जल प्रदाय में कोई ऐसी रोक या कमी होती है, जिसकी बाबत धारा 8 के अधीन प्रतिकर अनुज्ञेय है, इस आधार पर उक्त भूमि के लिए उसके द्वारा तत्पूर्व संदेय भाटक में उपशमन का दावा कर सकता है कि अवरोध के कारण भूधृति का मूल्य घट जाता है।

12. जल प्रदाय के प्रत्यावर्तन पर भाटक में वृद्धि—यदि ऐसी भूधृति के मूल्य में वृद्धि करने वाला जल प्रदाय उक्त भूमि में बाद में प्रत्यावर्तित किया जाता है तो, अभिधारी का भाटक, प्रत्यावर्तित जल प्रदाय के कारण ऐसी भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि की बाबत, ऐसी रकम तक बढ़ाया जा सकता है जो उस रकम से अनधिक है जो उपशमन के ठीक पहले थी।

ऐसी वृद्धि केवल प्रत्यावर्तित जल प्रदाय के कारण होगी, और अभिधारी के किसी अन्य आधार पर भाटक में वृद्धि के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

13. प्रतिकर का शोध्य होना—इस भाग के अधीन प्रतिकर के लिए संदेय धन की सभी राशियां परिवादित, रोके जाने, कमी या नुकसान की बाबत ऐसे प्रतिकर का दावा किए जाने पर तीन मास के पश्चात् शोध्य हो जाएंगी,

ब्याज—और उक्त तीन मास के पश्चात् ऐसी शेष असंदत्त राशि पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अनुज्ञप्ति किया जाएगा, उस दशा में सिवाय जहां ऐसी राशि का असंदाय दावेदार की जानबूझकर की गई उपेक्षा या उसे प्राप्त करने से इंकार के कारण हुआ है।

¹ अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए।

² अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए।

भाग 3

संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण

14. प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्ति आदि—कोई नहर अधिकारी, या नहर अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति,

नहर के पार्श्वस्थ भूमि पर, या ऐसी भूमि पर जिसमें से होकर किसी नहर के बनाए जाने की प्रस्थापना है, प्रवेश कर सकता है और उस पर सर्वेक्षण या तल मापन कर सकता है;

और अवमृदा को खोद सकता है और उसमें बोर कर सकता है;

और उपयुक्त भूमि चिह्न, समतल चिह्न और जल गेज बना सकता है और स्थापित कर सकता है ;

और, उक्त नहर अधिकारी के भारसाधन के अधीन किसी विद्यमान या परियोजित नहर से संबंधित किसी जांच के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सकता है;

भूमि को साफ करने की शक्ति—और, जहां ऐसी जांच अन्यथा पूरी नहीं की जा सकती है वहां ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के भाग को काट सकता है और साफ कर सकता है;

जल प्रदाय का निरीक्षण और विनियमन करने की शक्ति—और प्रदाय किए गए जल के उपयोग का निरीक्षण या विनियमन करने के, या उसके द्वारा सिंचित या जल दर से प्रभार्य भूमि का माप करने के, और ऐसी नहर के उचित विनियमन और प्रबंध के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि, भवन या जलसरणी पर भी, जिसके कारण कोई जल दर प्रभार्य है, प्रवेश कर सकता है;

गृह में आशयित प्रवेश की सूचना—परन्तु, यदि ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति किसी भवन या घिरे हुए आंगन या निवास गृह से लगे हुए उद्यान में, जिसे नहर से बहने वाला जल प्रदाय नहीं किया जाता है, प्रवेश की प्रस्थापना करता है तो वह ऐसे भवन, आंगन या उद्यान के अधिभोगी को अपने ऐसा करने के आशय की कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देगा ।

प्रवेश के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रतिकर—इस धारा के अधीन प्रत्येक प्रवेश की दशा में, नहर अधिकारी ऐसे प्रवेश के समय पर, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए प्रतिकर निविदत्त करेगा और इस प्रकार निविदत्त रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद की दशा में वह कलक्टर द्वारा विनिश्चय के लिए उसे तुरन्त निर्दिष्ट करेगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

15. मरम्मत के लिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवेश की शक्ति—किसी नहर में कोई दुर्घटना या दुर्घटना की आशंका होने की दशा में, नहर खण्ड अधिकारी या इस निमित्त उसके साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी नहर के पार्श्वस्थ भूमियों पर प्रवेश कर सकता है, और मरम्मत करने या ऐसी दुर्घटना को रोकने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संकर्म कर सकता है ।

भूमि को नुकसान के लिए प्रतिकर—ऐसी प्रत्येक दशा में, ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति उक्त भूमियों को किए गए सभी नुकसान के लिए उक्त भूमियों के स्वामी या अधिभोगियों को प्रतिकर निविदत्त करेगा । यदि ऐसा निविदान स्वीकार नहीं किया जाता है तो, नहर अधिकारी मामले को कलक्टर को निर्दिष्ट करेगा, जो नुकसान के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो राज्य सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1870¹ (1870 का 10) की धारा 43 के अधीन भूमि के अधिभोग के लिए निदेश दिया हो ।

16. नहर के जल का उपयोग करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन—किसी नहर के जल का उपयोग करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, नहर के उस खण्ड या उपखण्ड के जिससे जलसरणी प्रदाय की जानी है, खण्ड अधिकारी को, आवेदकों के खर्च पर जलसरणी निर्मित करने या उसमें अभिवृद्धि करने का अनुरोध करते हुए लिखित आवेदन कर सकते हैं ।

आवेदन की अन्तर्वस्तु—आवेदन में किए जाने वाले संकर्म, उनकी प्राक्कलित लगभग लागत, या उसके लिए वह रकम जो आवेदक संदाय करने के लिए रजामन्द हैं या यह कि क्या वे नहर खण्ड अधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली वास्तविक लागत संदाय करने का अनुबन्ध करते हैं और किस प्रकार संदाय किया जाएगा, कथित होगा ।

आवेदकों का संकर्म के खर्च के लिए दायित्व—जब नहर अधीक्षक अधिकारी को किसी आवेदन की अनुमति दी जाती है तब, कलक्टर के समक्ष आवेदन के सम्यक्तः प्रमाणित किए जाने के पश्चात् सभी आवेदक, पृथक् और संयुक्त रूप से उसमें उल्लिखित विस्तार तक ऐसे संकर्म के खर्च के लिए दायी होंगे ।

शोध्य रकम की वसूली—ऐसे आवेदन के निबंधनों के अधीन शोध्य होने वाली कोई रकम जो नहर खण्ड अधिकारी को, या उसके द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, जिस तारीख को वह शोध्य हो जाती है उसको या उसके पहले संदत्त

¹ अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।

नहीं की जाती है तो ऐसे अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

17. सरकार का नहरों को पार करने के साधन की व्यवस्था करना—राज्य सरकार के खर्चे पर पर निर्मित या अनुरक्षित नहरों को पार करने के उपयुक्त साधनों को ऐसे स्थानों पर जो पार्श्वस्थ भूमि के निवासियों की युक्तियुक्त सुविधा के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझे, राज्य सरकार के खर्चे पर व्यवस्था की जाएगी।

ऐसी भूमियों के कम से कम पांच स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव के कथन की प्राप्ति पर किसी नहर पर उपयुक्त क्रासिंग का प्रबन्ध नहीं किया गया है, कलक्टर उस मामले की परिस्थितियों की जांच करेगा और यदि वह सोचता है कि कथन साबित हो गया है तो, वह उस पर अपनी राय राज्य सरकार के विचार के लिए रिपोर्ट करेगा, और राज्य सरकार उसके निर्देश में ऐसे अध्यापय कराएगी जो वह उचित समझे।

18. जलसरणी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का सड़क आदि के पार जल के जाने के लिए संकर्म निर्माण—नहर खण्ड अधिकारी किसी जलसरणी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी सार्वजनिक मार्ग, नहर या जल-निकास जलसरणी बनाए जाने के पहले उपयोग में थे, पार ऐसी जलसरणी के जल के बहने के लिए उपयुक्त पुल, पुलियां या अन्य संकर्म निर्माण करने का या ऐसे संकर्म की मरम्मत करने का आदेश जारी कर सकता है।

ऐसा आदेश युक्तियुक्त अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें ऐसा निर्माण या मरम्मत पूरी की जाएगी;

उनके करने के अभाव में नहर अधिकारी निर्माण कर सकेंगे—और यदि, ऐसे आदेश की प्राप्ति के पश्चात्, वे व्यक्ति जिनको वह सम्बोधित है, उक्त कालावधि के अन्दर, उक्त नहर अधिकारी के समाधानपर्यन्त ऐसे संकर्म का निर्माण या मरम्मत नहीं कर सकते हैं तो वह, नहर अधीक्षक अधिकारी के पूर्वानुमोदन से स्वयं उसका निर्माण या मरम्मत कर सकता है;

और खर्चा वसूल करना—और यदि उक्त व्यक्ति, जब अपेक्षा की जाए, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा घोषित मरम्मत या निर्माण का खर्चा संदाय नहीं कर सकते हैं तो, नहर खण्ड अधिकारी की मांग पर वह रकम, उनसे कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

19. जलसरणी का संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच दावों का समायोजन—यदि, किसी जलसरणी के निर्माण या अनुरक्षण के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार या अन्य व्यक्तियों के साथ जलसरणी का संयुक्त रूप से उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के खर्चे के अपने अंश का संदाय करने, या ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिए आवश्यक किसी संकर्म को निष्पादित करने के अपने अंश की उपेक्षा करता है या उससे इंकार करता है तो नहर खण्ड या उपखण्ड अधिकारी ऐसी उपेक्षा या इंकार से क्षतिग्रस्त किसी व्यक्ति से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, सभी सम्पृक्त पक्षकारों पर यह सूचना तामील करेगा कि तामील से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, वह मामले का अन्वेषण करेगा, और उसी अवधि की समाप्ति पर, तदनुसार मामले का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे।

ऐसे आदेश की अपील आयुक्त को हो सकेगी जिसका उस पर आदेश अन्तिम होगा।

शोध्य पाई जाने वाली रकम की वसूली—विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर संदाय किए जाने के लिए ऐसे आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई राशि, यदि ऐसी कालावधि के अन्दर संदत्त नहीं की जाती है, और यदि आदेश प्रवृत्त बना रहता है तो, उसका संदाय करने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति से कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

20. बीच की जलसरणी द्वारा जल प्रदाय—जब कभी नहर खण्ड अधिकारी को किसी नहर से जल प्रदाय के लिए आवेदन किया जाता है, और उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा प्रदाय करना समीचीन है और वह किसी विद्यमान जलसरणी द्वारा किया जाना चाहिए तो, वह ऐसी जलसरणी का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को, ऐसे दिन जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से कम न हो, यह हेतुक दर्शित करने की सूचना देगा कि क्यों उक्त प्रदाय इस प्रकार न किया जाए; और ऐसे दिन जांच करने के पश्चात् नहर खण्ड अधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या और किन शर्तों पर ऐसी जलसरणी द्वारा उक्त प्रदाय किया जाएगा।

जब ऐसा अधिकारी यह अवधारित करता है कि यथापूर्वोक्त किसी जलसरणी द्वारा नहर जल प्रदाय किया जा सकता है तब, उसका विनिश्चय, नहर अधीक्षक अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने या उपान्तरित किए जाने पर, आवेदक पर और उक्त जलसरणी के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर आवद्धकर होगा।

ऐसा आवेदक ऐसी जलसरणी का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उसने ऐसी जलसरणी में, जलसरणी के माध्यम से उसको जल प्रदाय किए जाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने के खर्चे और ऐसी जलसरणी की प्रथम लागत का ऐसा हिस्सा जो नहर अधीक्षक या खण्ड अधिकारी अवधारित करे, संदाय न कर दिया हो।

ऐसा आवेदक ऐसी जलसरणी के जब तक वह उसका उपयोग करता है अनुरक्षण के खर्चे के हिस्से के लिए भी दायी होगा।

21. नई जलसरणी के निर्माण के लिए आवेदन—कोई व्यक्ति जो नई जलसरणी का निर्माण करना चाहता है, नहर खण्ड अधिकारी को एक लिखित आवेदन दे सकता है जिसमें वह कथित होगा—

(1) कि उसने उस भूमि के स्वामियों से जिसमें से होकर वह ऐसी जलसरणी को ले जाना चाहता है, उतनी भूमि के जितनी ऐसी जलसरणी के लिए आवश्यक हो, अधिभोग के अधिकार को अर्जित करने के लिए विफल प्रयास किया है;

(2) कि वह यह चाहता है कि उक्त नहर अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्च पर, ऐसा अधिकार अर्जित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करे;

(3) कि वह ऐसे अधिकार के अर्जन में और ऐसी जलसरणी के निर्माण में होने वाली सभी खर्चों को चुकाने में समर्थ है।

22. इस पर नहर अधिकारी की प्रक्रिया—यदि नहर खण्ड अधिकारी यह समझता है कि :—

(1) ऐसी जलसरणी का निर्माण समीचीन है, और

(2) आवेदन में के कथन सत्य हैं,

तो वह, आवेदक से ऐसा निक्षेप करने की मांग करेगा जो नहर खण्ड अधिकारी प्रारंभिक कार्यवाहियों के खर्चों को चुकाने के लिए और उस प्रतिकर की रकम को चुकाने के लिए आवश्यक समझे जो वह धारा 28 के अधीन शोध्य हो जाने के लिए संभाव्य समझे;

और, ऐसा निक्षेप किए जाने पर, वह उक्त जलसरणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संरक्षण के लिए जांच कराएगा, और उस भूमि को चिह्नित कराएगा, जिसका उसकी राय में, उसके निर्माण के लिए अधिभोग करना आवश्यक हो, और ऐसे प्रत्येक ग्राम में जिसमें से होकर उस जलसरणी को ले जाना प्रस्थापित है, एक सूचना प्रकाशित करेगा कि ऐसी भूमि का इतना भाग जो ऐसे ग्राम का है इस प्रकार चिह्नित किया गया है, और ऐसी सूचना की एक प्रति ऐसे प्रत्येक जिले के कलक्टर को भेजेगा जिसमें ऐसी भूमि का कोई भाग अवस्थित है।

23. विद्यमान जलसरणी के अन्तरण के लिए आवेदन—कोई व्यक्ति जो यह चाहता है कि विद्यमान जलसरणी उसके वर्तमान स्वामी से उसको अन्तरित कर दी जाए, नहर खण्ड अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकता है जिसमें यह कथन होगा कि :—

(1) उसने ऐसी जलसरणी के स्वामी से ऐसा अन्तरण प्राप्त करने का विफल प्रयास किया है;

(2) वह यह चाहता है कि उक्त नहर अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्च पर, ऐसे अन्तरण की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कार्य करे;

(3) वह ऐसे अन्तरण का खर्चा चुकाने में समर्थ है।

इस पर प्रक्रिया—यदि नहर खण्ड अधिकारी यह समझता है कि—

(क) उक्त अन्तरण ऐसी जलसरणी से सिंचाई के अच्छे प्रबन्ध के लिए आवश्यक है, और

(ख) आवेदन में किए गए कथन सत्य हैं,

तो वह, आवेदक से ऐसा निक्षेप करने की मांग करेगा जो नहर खण्ड अधिकारी प्रारंभिक कार्यवाहियों के खर्चों को चुकाने के लिए और उस प्रतिकर की रकम को चुकाने के लिए आवश्यक समझे जो वह धारा 28 के अधीन शोध्य हो जाने के लिए संभाव्य समझे;

और ऐसा निक्षेप किए जाने पर, वह आवेदन की सूचना प्रत्येक क्रम में प्रकाशित करेगा, और सूचना की एक प्रति प्रत्येक ऐसे जिले के, जिसमें से होकर ऐसी जलसरणी जाती है, कलक्टर को भेजेगा।

24. आवेदित निर्माण या अन्तरण पर आक्षेप—यथास्थिति, धारा 22 या धारा 23 के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से अन्दर, उस भूमि या जलसरणी से, जिसके प्रति सूचना में निर्देश है, हितबद्ध कोई व्यक्ति कलक्टर को अर्जी द्वारा उस निर्माण या अन्तरण पर जिसके लिए आवेदन दिया गया है, अपने आक्षेपों का कथन करते हुए आवेदन कर सकता है।

कलक्टर या तो अर्जी को स्वीकार कर सकता है या नहर खण्ड अधिकारी को उस स्थान और समय की पूर्व सूचना देते हुए जहां जांच की जाएगी, आक्षेपों की विधिमान्यता पर जांच की कार्यवाही कर सकता है।

कलक्टर इस धारा के अधीन उसके द्वारा पारित सभी आदेशों को और उसके आधारों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

25. कब आवेदक को अधिभोग दिया जा सकता है—यदि ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया जाता है या (जहां ऐसा आक्षेप किया जाता है) यदि कलक्टर उसे नामंजूर कर देता है तो वह, नहर खण्ड अधिकारी को उस प्रभाव की सूचना देगा, और उक्त आवेदक को, यथास्थिति, चिह्नित भूमि का या अन्तरित की जाने वाली जलसरणी का अधिभोग तुरन्त देने की कार्यवाही करेगा।

26. जब आक्षेप का विधिमान्य होना अभिनिर्धारित किया जाता है तब प्रक्रिया—यदि कलक्टर यथापूर्वोक्त किए गए किसी आक्षेप को विधिमान्य समझता है तो वह नहर खण्ड अधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और यदि ऐसा अधिकारी ठीक समझे तो वह, धारा 21 के अधीन आवेदन की दशा में, इस प्रकार चिह्नित भूमि की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है और धारा 22 के अधीन नई सूचना दे सकता है; और इसमें इसके पहले उपबन्धित प्रक्रिया ऐसी सूचना को लागू होगी, और उस पर कलक्टर जैसा पहले उपबन्धित है कार्यवाही करेगा।

27. जब नहर अधिकारी कलक्टर से असहमत हो तब प्रक्रिया—यदि नहर अधिकारी कलक्टर से असहमत है तब, मामले को आयुक्त के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा, और कलक्टर, यदि ऐसे विनिश्चय के लिए इस प्रकार निदेश किया जाता है तो धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त आवेदक को, यथास्थिति, इस प्रकार चिह्नित भूमि का या अन्तरित की जाने वाली जलसरणी का अधिभोग दिलाएगा।

28. अधिभोग प्राप्त करने के पहले आवेदक द्वारा खर्चों का संदाय—किसी आवेदक को ऐसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि उसने कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसी रकम संदाय न कर दी हो कलक्टर, इस प्रकार अधिभोग में दी गई या अन्तरित भूमि या जलसरणी के लिए और ऐसे अधिभोग या अन्तरण के अनुषंगी सभी खर्चों सहित ऐसी भूमि के चिह्नित किए जाने या अधिभोग द्वारा कारित किसी नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में, शोध्य अवधारित करे।

प्रतिकर नियत करने की प्रक्रिया—कलक्टर इस धारा के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1870¹ (1870 का 10) के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करेगा; किन्तु यदि प्रतिकर पाने वाला व्यक्ति ऐसा चाहे तो वह, ऐसे प्रतिकर को अधिभोग में ली गई या अन्तरित भूमि या जलसरणी की बाबत संदेय भाटक प्रभार के रूप में अधिनिर्णीत कर सकता है।

प्रतिकर और खर्चों की वसूली—यदि ऐसा प्रतिकर और खर्चें उनको पाने के हकदार व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर संदाय नहीं किए जाते हैं तो वह रकम कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और वसूल की जाने पर, उसे पाने के हकदार व्यक्ति को संदाय की जाएगी।

29. जिसे अधिभोग दिलाया गया है उस आवेदक पर आबद्धकर शर्तें—जब कभी ऐसे आवेदक को यथापूर्वोक्त किसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग दिया जाता है तब, उस पर और उसके हित प्रतिनिधियों पर निम्नलिखित नियम और शर्तें आबद्धकर होंगी—

प्रथम—ऐसी जलसरणी के, उसके विनिर्माण के पहले से विद्यमान जलसरणियों के और उसके द्वारा अन्तःरुद्ध जल-निकास के पार जाने के लिए, और पड़ोस की भूमि की सुविधा के लिए उसके आर-पार उचित संचार व्यवस्था करने के लिए, सभी आवश्यक संकर्म आवेदक द्वारा निर्मित किए जाएंगे और नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त उसके द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा अनुरक्षित किए जाएंगे।

द्वितीय—धारा 22 के उपबन्धों के अधीन किसी जलसरणी के लिए अधिभोग में रखी गई भूमि का उपयोग केवल ऐसी जलसरणी के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

तृतीय—प्रस्थापित जलसरणी नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त आवेदक के उस भूमि को अधिभोग में लिए जाने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर पूरी की जाएगी।

उन दशाओं में जिनमें भाटक प्रभार के निबन्धनों पर भूमि का अधिभोग किया जाता है या जलसरणी अन्तरित की जाती है।

चतुर्थ—आवेदक या उसका हित प्रतिनिधि, जब तब वह ऐसी भूमि या जलसरणी या अधिभोग करता है, उसके लिए ऐसी दर पर और ऐसे दिन भाटक का संदाय करेगा जो कलक्टर द्वारा आवेदक को अधिभोग देते समय अवधारित किए जाएं।

पंचम—यदि इन नियमों में से किसी के भंग के कारण भूमि को अधिभोग में रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो, उक्त भाटक को संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा जब तक आवेदक या उसका हित प्रतिनिधि भूमि को उसकी आरम्भिक दशा में प्रत्यावर्तित न कर दे, या जब तक वह उक्त भूमि को की गई क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में कलक्टर द्वारा अवधारित रकम कलक्टर द्वारा अवधारित व्यक्तियों को संदाय न कर दे।

षष्ठ—कलक्टर, ऐसे भाटक या प्रतिकर को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के आवेदन पर, शोध्य भाटक की रकम अवधारित कर सकता है या ऐसे प्रतिकर की रकम निर्धारित कर सकता है; और यदि ऐसे भाटक या प्रतिकर का आवेदक या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा संदाय नहीं किया जाता है तो, कलक्टर वह रकम, उसके शोध्य हो जाने की तारीख से छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो, और वसूल हो जाने पर उसे उस व्यक्ति को संदाय करेगा जिसको वह शोध्य है।

यदि इस धारा द्वारा विहित किसी नियम और शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है,

या इस अधिनियम के अधीन निर्मित या अन्तरित किसी जलसरणी का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है तो,

आवेदक या उसके हित प्रतिनिधि का, ऐसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग करने का अधिकार आत्यन्तिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

¹ अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए।

30. विस्तार और परिवर्तनों के लिए अधिभोग को लागू होने वाली प्रक्रिया—इसमें इसके पहले जलसरणी के निर्माण के लिए भूमि के अधिभोग के लिए उपबन्धित प्रक्रिया, जलसरणी के विस्तार या परिवर्तन के लिए और जलसरणी की सफाई से निकाली मृदा को जमा करने के लिए भूमि के अधिभोग को लागू होगी।

भाग 4

जल प्रदाय

31. लिखित संविदा के अभाव में जल प्रदाय का नियमों के अधीन होना—लिखित संविदा के अभाव में, या जिस सीमा तक किसी ऐसी संविदा का विस्तार नहीं है वहां, नहर जल का प्रत्येक प्रदाय इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विहित दरों पर और शर्तों के अधीन दिया गया समझा जाएगा।

32. शर्तें—ऐसी संविदाएं और नियम निम्नलिखित शर्तों से सुसंगत होंगे :—

(क) **जल प्रदाय को रोकने की शक्ति के बारे में**—नहर खण्ड अधिकारी किसी जलसरणी को या किसी व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, जल प्रदाय नहीं रोकेंगे :—

- (1) जब कभी और जितने समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा आदिष्ट किसी संकर्म को करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रदाय को रोकना आवश्यक है, और इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ले ली गई है;
- (2) ठीक हालत में नहीं रखी जाती है तब उससे जल के अपचय निकास को रोकने के लिए;
- (3) नहर खण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत कालावधि में;

(ख) **प्रदाय के न होने या रोके जाने की दशा में प्रतिकर के दावे**—राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर किसी कारणवश या नहर में किसी मरम्मत, परिवर्तन या वृद्धि के, या उसमें जल के उचित बहाव को विनियमित करने के लिए किए गए उपायों के, या सिंचाई की स्थापित सरणी बनाए रखने के, जो नहर खण्ड अधिकारी आवश्यक समझे, कारणवश किसी नहर में जल के न होने या रोके जाने से हुई हानि की बाबत प्रतिकर के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसी हानि उठाने वाला व्यक्ति जल के उपयोग के लिए संदेय साधारण प्रभार से ऐसे छूट का दावा कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) **अन्य कारणों से अवरोध के कारण दावे**—यदि इसके ठीक पहले के खण्ड में वर्णित रीति से भिन्न किसी रीति में किसी नहर से सिंचित किसी भूमि में जल का प्रदाय अवरुद्ध होता है तो, ऐसी भूमि का अधिभोगी या स्वामी ऐसे अवरोध से होने वाली हानि के लिए कलक्टर को प्रतिकर के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है, और कलक्टर अर्जीदार को ऐसी हानि के लिए उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है;

(घ) **प्रदाय की अवधि**—जब नहर का जल किसी एक फसल की सिंचाई के लिए प्रदाय किया जाता है तब, ऐसे जल के प्रयोग की अनुज्ञा तभी तक जारी मानी जाएगी जब तक फसल पक नहीं जाती है, और उसी फसल को लागू होने वाली मानी जाएगी; किन्तु, यदि वह एक वर्ष के अन्दर उसी भूमि पर उगाई जाने वाली दो या अधिक फसलों की सिंचाई के लिए प्रदाय किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा सिंचाई के प्रारम्भ से एक वर्ष तक चालू मानी जाएगी, और ऐसी फसलों को ही लागू होगी जो उस वर्ष के अन्दर पक जाती हैं;

(ङ) **नहर जल के उपयोग के अधिकार का विक्रय या उपपट्टा**—किसी नहर के जल या किसी नहर से सम्बन्धित किसी संकर्म, भवन या भूमि का उपयोग करने का हकदार कोई व्यक्ति, नहर अधीक्षक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ऐसे उपयोग के अपने अधिकार का विक्रय या उपपट्टा या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा :

परन्तु इस खण्ड का पूर्वगामी भाग किसी खेतिहर अभिधारी द्वारा धृत भूमि की सिंचाई के लिए जलसरणी के स्वामी द्वारा प्रदाय किए गए जल के ऐसे अभिधारी द्वारा उपयोग को लागू नहीं होगा;

जल के लिए संविदा का भूमि के साथ अन्तरण—किन्तु राज्य सरकार और किसी स्थावर सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी के बीच, ऐसी सम्पत्ति को नहर जल के प्रदाय के बारे में हुई सभी संविदाएं, उसके साथ अन्तरणीय होंगी, और जब कभी ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण होता है तब इस प्रकार अन्तरित समझी जाएंगी।

(च) **उपयोग से अधिकार का अर्जित न होना**—भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877¹ (1877 का 15) के भाग 4 के अधीन नहर के जल के उपयोग का कोई अधिकार न तो अर्जित किया जाएगा और न अर्जित किया गया समझा जाएगा, और न ही राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जैसा लिखित संविदा के निबन्धनों के अनुसार हो उसके सिवाय, जल प्रदाय करने के लिए आबद्ध होगी।

¹ अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) देखिए।

भाग 5

जल दर

33. जब अप्राधिकृत रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है तब दायित्व—यदि जलसरणी से प्रदाय किए गए जल का किसी अप्राधिकृत रीति में उपयोग किया जाता है, और यदि वह व्यक्ति जिसके कार्य या उपेक्षा से ऐसा उपयोग हुआ है पहचाना नहीं जा सकता है तो,

वह व्यक्ति जिसकी भूमि पर ऐसा जल बहा है यदि उस भूमि को उससे फायदा पहुंचा है,

या यदि ऐसा व्यक्ति पहचाना नहीं जा सकता है, या यदि ऐसी भूमि को उससे फायदा नहीं पहुंचा है तो, ऐसी जलसरणी से प्रदाय किए गए जल की बाबत प्रभार्य सभी व्यक्ति, ऐसे उपयोग के लिए किए गए प्रभार के लिए, यथास्थिति, दायी होंगे, या संयुक्त रूप से दायी होंगे।

34. जल का अपचय होने पर दायित्व—यदि जलसरणी से प्रदाय किए गए जल का अपचय होने दिया जाता है और यदि नहर खण्ड अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् उस व्यक्ति का पता नहीं लगता है जिसके कार्य या उपेक्षा से जल का ऐसा अपचय हुआ है तो, ऐसी जलसरणी से प्रदाय किए जाने वाले जल की बाबत प्रभार्य सभी व्यक्ति इस प्रकार अपचय किए गए जल की बाबत प्रभार के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे।

35. प्रभारों का शास्तियों के अतिरिक्त वसूल हो सकना—जल के अप्राधिकृत उपयोग या अपचय के लिए सभी प्रभार ऐसा उपयोग या अपचय के कारण उपगत शास्तियों के अतिरिक्त वसूल किए जा सकेंगे।

धारा 33 और 34 के अधीन प्रश्नों का विनिश्चय—जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी को अपील के अधीन, या ऐसी अन्य अपील के अधीन, जो धारा 75 के अधीन उपबन्धित की जाए, धारा 33 या धारा 34 के अधीन सभी प्रश्नों का, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

36. जल के लिए अधिभोगी पर प्रभार के अवधारण का ढंग—भूमि के अधिभोगियों को सिंचाई के प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए नहर जल के लिए प्रभारित किए जाने वाले जल की दर राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित की जाएगी, और ऐसे अधिभोगी जो जल ग्रहण करते हैं तदनुसार संदाय करेंगे।

“अधिभोगी दर”—इस प्रकार प्रभारित दर “अधिभोगी दर” कहलाएगी।

[इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट नियम यह विहित और अवधारित कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिभोगी समझे जाएंगे, और अभिधारियों के और उन व्यक्तियों के, जिन्हें अभिधारियों ने अपनी भूमि उपपट्टे पर दी हो, या स्वत्वधारियों के और उन व्यक्तियों के जिनको स्वत्वधारियों ने अपने द्वारा धारित भूमि को कृषि अधिभोग में पट्टे पर दिया हो, अधिभोगी दर के संदाय की बाबत पृथक्-पृथक् दायित्व भी अवधारित कर सकते हैं।]

37. “स्वामी दर”—अधिभोगी दर के अतिरिक्त, “स्वामी दर” कहलाने वाली एक और दर, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार, नहर सिंचित भूमि के स्वामियों पर, उस फायदे की बाबत, जो वे ऐसी सिंचाई से प्राप्त करते हैं, अधिरोपित की जा सकती है।

38. स्वामी दर की रकम—स्वामी दर उस राशि से अधिक नहीं होगी जो, भू-राजस्व के निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, ऐसी भूमि पर नहरी सिंचाई के कारण उसके वार्षिक मूल्य या उसकी उपज में वृद्धि के कारण निर्धारित की जाए। और केवल इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि जो स्थायी रूप से व्यवस्थापित है या राजस्व मुक्त है, यह समझी जाएगी मानो वह अस्थायी रूप से व्यवस्थापित है और राजस्व के संदाय की दायी है।

39. स्वामी दर कब प्रभार्य नहीं होगी—सिंचाई दर पर भू-राजस्व के संदाय के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित स्वामी या भूमि के अधिभोगी पर ऐसे निर्धारण के चालू रहने के दौरान स्वामी दर प्रभार्य नहीं होगी।

40. कब अधिभोगी स्वामी दर और अधिभोगी दर दोनों का संदाय करेगा—यदि ऐसी भूमि स्वामी के अधिभोग में है,

या किसी अभिधारी के अधिभोग में है जिसका भाटक इस आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता है कि भूमि की उपज का मूल्य या भूमि की उत्पादन शक्ति सिंचाई द्वारा वृद्धिगत हुई है तो,

ऐसा स्वामी या अभिधारी स्वामी दर और अधिभोगी दर दोनों का संदाय करेगा।

41. स्वामी दर का प्रभाजन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति—अधिभोगी के अधिकार वाले अभिधारी की दशा में, राज्य सरकार को ऐसे अधिभोगी और उसके भू-स्वामी के बीच, भूमि में उनमें से प्रत्येक के फायदाप्रद हित के विस्तार के अनुपात में स्वामी दर विभाजित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी।

¹ 1899 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

² पंजाब अधिधृति अधिनियम, 1887 (1887 का 16) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पंजाब में धारा 40 से 43 निरसित की गई।

142. स्वामी कब स्वामी दर देगा—यदि भूमि का स्वामी अधिभोगी नहीं है, किन्तु उसे अधिभोगी का भाटक इस आधार पर बढ़ाने की शक्ति है कि उपज का या भूमि की उत्पादक शक्ति का मूल्य सिंचाई द्वारा वृद्धिगत हुआ है तो;

या यदि, जब भाटक की रकम नियत की गई थी तब भूमि नहर से सिंचित थी तो, स्वामी दर का संदाय स्वामी करेगा।

143. भू-स्वामी के बढ़ाने के अधिकार पर नहर सिंचाई के प्रारम्भ होने का प्रभाव—यदि व्यवस्थापन का पुनरीक्षण, भाटक बढ़ाने के लिए वाद ग्रहण करने का आधार है, तो किसी भूमि में नहर सिंचाई प्रारम्भ होने का, भू-स्वामी के ऐसी भूमि पर अधिभोग के अधिकार वाले अभिधारी के भाटक को पुनः बढ़ाने के अधिकार पर इस प्रकार प्रभाव होगा मानो व्यवस्थापन का पुनरीक्षण हुआ है जिसके अधीन ऐसी भूमि की बाबत संदेय राजस्व वृद्धिगत हुआ है।

44. जल दर किसके द्वारा संदेय होगी जब अनेक स्वामियों द्वारा धारित भूमियों पर प्रभारित हो—जहां ऐसी भूमि पर जल दर प्रभारित की जाती है जो अनेक संयुक्त स्वामियों द्वारा धारित है वहां वह ऐसे प्रबन्धक या अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जो ऐसी भूमि का भाटक या लाभ प्राप्त करता है, और उसके द्वारा विभाजन के पूर्व ऐसे भाटक या लाभ में से काटी जा सकती है, या उसके द्वारा ऐसी दर के लिए दायी व्यक्तियों से ऐसी रीति से वसूल की जा सकती है जो ऐसे भाटक या लाभ पर होने वाले प्रभारों की वसूली के लिए रूढ़ि के अनुसार हो।

प्रभारों की वसूली

45. प्रमाणित शोध्य राशियों का भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता—कोई राशि, जो इस भाग के अधीन विधिपूर्णतः शोध्य है और जिसका नहर खण्ड अधिकारी द्वारा इस प्रकार शोध्य होना प्रमाणित है, और जो उस दिन के पश्चात् जिस दिन वह शोध्य हो जाती है, असदत्त रहती है, कलक्टर द्वारा उसके लिए दायी व्यक्ति के इस प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

46. नहरी देय के संग्रह के लिए संविदा करने की शक्ति—नहर खण्ड अधिकारी या कलक्टर किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य पक्षकार द्वारा संदेय किसी राशि के संग्रह और ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदाय करने के लिए करार कर सकता है।

जब ऐसा करार कर लिया गया हो तब, ऐसा व्यक्ति वाद द्वारा ऐसी राशि वसूल कर सकता है मानो वह उसके प्रति शोध्य ऋण है, या उस भूमि, संकर्म या भवन के कारण, जिसकी बाबत ऐसी राशि संदेय है, या जिसके लिए या जिसमें नहर जल प्रदाय किया गया है या उपयोग किया गया है, उसको शोध्य भाटक का बकाया है।

यदि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन उसके द्वारा संगृहीत किसी राशि का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसी राशि कलक्टर द्वारा धारा 45 के अधीन उससे वसूल की जा सकती है; और यदि ऐसी राशि या उसका कोई भाग उक्त अन्य पक्षकार द्वारा तब भी शोध्य हो तो, वह शोध्य राशि या उसका भाग ऐसी ही रीति में ऐसे अन्य पक्षकार से कलक्टर द्वारा वसूल किया जा सकता है।

47. लम्बरदारों से नहरी देय का संग्रह करने की अपेक्षा—कलक्टर, लम्बरदार से या किसी सम्पदा के भू-राजस्व के संदाय के लिए वचनबद्ध किसी व्यक्ति से, किसी भूमि या ऐसी सम्पदा में जल की बाबत किसी अन्य पक्षकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय राशियों का संग्रह और संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।

ऐसी राशियां कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकती हैं मानो वे ऐसी सम्पदा से उस व्यतिकारी के अंश की बाबत शोध्य भू-राजस्व की बकाया हों;

और अधीनस्थ जमींदारों, रैयतों, 2[अभिधारियों या उपअभिधारियों] से ऐसी राशियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा लम्बरदार या व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और ऐसे नियमों के अधीन होगा जो भूमि के भाटक या भू-राजस्व के अंश के उसके द्वारा संग्रह की बाबत तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अधिकथित हों।

राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी—

- (क) इस धारा के अधीन राशियों का संग्रह करने वाले व्यक्तियों को पारिश्रमिक देने के लिए; या
- (ख) ऐसे संग्रह करने में उनके द्वारा उचित रूप में उपगत व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए; या
- (ग) ऐसे दोनों प्रयोजनों के लिए।

48. जुर्मानों का धारा 45, 46 और 47 से अपवर्जन—धारा 45, 46 या 47 की कोई बात जुर्मानों को लागू नहीं होती है।

¹ पंजाब अधिधृति अधिनियम, 1887 (1887 का 16) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पंजाब में धारा 40 से 43 निरसित की गई।

² 1899 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा "या अभिधारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 6

नहरी नौपरिवहन

49. नियमों का उल्लंघन करने वाले जलयानों का निरोध—कोई जलयान जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के प्रतिकूल किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन करता है, या इस प्रकार प्रवेश या नौपरिवहन करता है कि नहर को या उसमें अन्य जलयानों को संकट कारित होता है, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा या इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकता है या रोक रखा जा सकता है या दोनों, हटाया भी जा सकता है और रोक रखा भी जा सकता है।

नुकसान पहुंचाने वाले जलयानों के स्वामियों का दायित्व—किसी नहर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी जलयान का, या इस धारा के अधीन हटाए गए या रोक रखे गए किसी जलयान का स्वामी, राज्य सरकार को ऐसी राशि संदाय करने का दायी होगा जो नहर खण्ड अधिकारी नहर अधीक्षक अधिकारी के अनुमोदन से, यथास्थिति, ऐसी क्षति को ठीक करने के लिए या ऐसे हटाए जाने या रोक रखने के व्यय को चुकाने के लिए आवश्यक होना अवधारित करे।

50. नहरों में नौपरिवहन में अपराधों के लिए जुर्माने की वसूली—किसी जलयान के स्वामी पर या ऐसे स्वामी के किसी सेवक या अभिकर्ता पर या ऐसे जलयान के भारसाधक अन्य व्यक्ति पर, ऐसे जलयान के नौपरिवहन की बाबत किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, या तो ऐसी रीति में वसूल किया जा सकता है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता¹ द्वारा विहित हो, या, यदि जुर्माना अधिरोपित करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश करे तो, इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह ऐसे जलयान की बाबत शोध्य प्रभार हो।

51. प्रभार संदाय करने में असफल रहने पर जलयान को अभिग्रहण करने और रोक रखने की शक्ति—यदि इस भाग के उपबन्धों के अधीन किसी जलयान की बाबत शोध्य कोई प्रभार मांगे जाने पर उसका संग्रह करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय नहीं किया जाता है तो, नहर खण्ड अधिकारी ऐसे जलयान को और उसके फर्नीचर को अभिगृहीत कर सकता है और रोक सकता है जब तक इस प्रकार शोध्य प्रभार, ऐसे अभिग्रहण और रोक रखने के कारण होने वाले सभी व्यय और अतिरिक्त प्रभारों सहित पूर्ण रूप से संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं।

52. स्थोरा या माल का अभिग्रहण करने की शक्तियां यदि उनके प्रभार संदत्त नहीं किए गए हों—यदि किसी सरकारी जलयान में किसी नहर पर वहन किए गए, या किसी नहर के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में रखे गए भाण्डागार में या भूमि पर भण्डारकरण किए गए किसी स्थोरा या माल की बाबत इस भाग के उपबन्धों के अधीन शोध्य प्रभार उसे संग्रह करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को मांगे जाने पर संदत्त नहीं किया जाता है तो, नहर खण्ड अधिकारी ऐसे स्थोरा या माल का अभिग्रहण कर सकता है और उसे तब तक रोके रख सकता है जब तक ऐसे अभिग्रहण और रोक रखने के कारण होने वाले सभी व्यय और अतिरिक्त प्रभारों सहित शोध्य प्रभार पूर्णतः संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं।

53. अभिग्रहण के पश्चात् ऐसे प्रभार की वसूली के लिए प्रक्रिया—धारा 51 या धारा 52 के अधीन किसी अभिग्रहण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर, उक्त नहर अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को यह सूचना देगा कि वह संपत्ति या उसका कोई भाग, जैसा आवश्यक हो, सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन को, किन्तु सूचना की तारीख से पंद्रह दिन से पहले नहीं, उस दावे की जिसके कारण ऐसी सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है, तुष्टि के लिए बेच दी जाएगी यदि इस प्रकार निश्चित दिन के पहले दावा चुका न दिया जाए।

और, यदि ऐसा दावा चुका नहीं दिया जाता है तो, उक्त नहर अधिकारी, ऐसे दिन, अभिगृहीत सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग विक्रय करेगा जो ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के व्यय सहित शोध्य रकम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

परन्तु किसी जलयान के फर्नीचर का, किसी स्थोरा या माल का उससे अधिक भाग विक्रय नहीं किया जाएगा जो जहां तक हो सके ऐसे जलयान, स्थोरा या माल की बाबत शोध्य रकम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

ऐसे फर्नीचर, स्थोरा या माल और विक्रय आगम का अवशिष्ट भाग अभिगृहीत सम्पत्ति के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के हवाले कर दिए जाएंगे।

54. त्यक्त यानों और बिना दावा किए गए माल की बाबत प्रक्रिया—यदि कोई जलयान किसी नहर में त्यक्त पाया जाता है या किसी नहर पर सरकारी जलयान में वहन किया गया या नहर के प्रयोजन के लिए अधिभोग में रखे गए भाण्डागार में या भूमि पर भण्डारकरण किया गया स्थोरा या माल दो मास की कालावधि के लिए बिना दावे के छोड़ दिया जाता है तो नहर खण्ड अधिकारी उसका कब्जा ले सकता है।

इस प्रकार कब्जा लेने वाला अधिकारी एक सूचना प्रकाशित कर सकता है, कि यदि ऐसे जलयान और उसकी अन्तर्वस्तु का या ऐसे स्थोरा या माल का, उस सूचना में निश्चित दिन के पहले, जो ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के पहले नहीं होगा, दावा नहीं किया जाता है तो वह, उसका विक्रय कर देगा; और यदि ऐसे जलयान, अन्तर्वस्तु, स्थोरा या माल का इस प्रकार दावा नहीं किया जाता है तो, वह सूचना में निश्चित दिन के पश्चात् किसी भी समय, उसका विक्रय करने की कार्यवाही कर सकता है।

¹ अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए।

विक्रय आगम का व्ययन—उक्त जलयान और उसकी अन्तर्वस्तु, और उक्त स्थोरा या माल, यदि अविक्रीत है या, यदि विक्रय हो गया है तो, विक्रय आगम, कब्जा लेने और विक्रय के कारण नहर खण्ड अधिकारी द्वारा उपगत सभी पथकर प्रभार और व्यय, संदाय करने के पश्चात् नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त उसका स्वामित्व साबित कर दिए जाने पर उसके स्वामी के हवाले कर दिए जाएंगे।

यदि नहर खण्ड अधिकारी को सन्देह है कि ऐसी सम्पत्ति का आगम किसके हवाले किया जाए तो वह यह निदेश दे सकता है कि सम्पत्ति यथापूर्वोक्त विक्रय की जाएगी, और आगम जिला खजाने में संदत्त किए जाएंगे जहां वे तब तक धारण किए जाएंगे जब तक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके अधिकार का विनिश्चय न किया जाए।

भाग 7

जल-निकास

55. बाधाओं का प्रतिषेध करने या उन्हें हटाने का आदेश देने की शक्ति—जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भूमि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुविधा को किसी नदी, सरिता या जल-निकास वाहिका को बाधित करने से कोई क्षति हो सकती है या हुई है तो, ऐसी सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में परिनिश्चित सीमा के अन्दर किसी बाधा का निर्माण करने का प्रतिषेध कर सकती है या ऐसी सीमा के अन्दर, ऐसी बाधा को हटाने का या अन्य उपान्तर करने का आदेश दे सकती है।

तब ऐसी नदी, सरिता या जल-निकास वाहिका का उतना भाग जो ऐसी सीमा के अन्दर समाविष्ट है, धारा 3 में यथापरिभाषित जल-निकास संकर्म समझा जाएगा।

56. प्रतिषेध के पश्चात् बाधा को हटाने की शक्ति—नहर खण्ड अधिकारी, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के पश्चात् ऐसी बाधा कारित करने वाले या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा नियत समय के अन्दर उसे हटाने या उपान्तरित करने का आदेश जारी कर सकता है।

यदि इस प्रकार नियत समय के अन्दर, ऐसा व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता है तो, उक्त नहर अधिकारी स्वतः बाधा को हटा सकता है या उपान्तरित कर सकता है और यदि वह व्यक्ति जिसको आदेश जारी किया गया था, जब मांग की जाती है तब, ऐसे हटाने या उपान्तर में अन्तर्वलित व्यय का संदाय नहीं करता है तो, ऐसे व्यय उससे या उसके हित प्रतिनिधि से कलक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे।

57. सुधार संकर्मों के लिए स्कीमों का बनाया जाना—जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं भूमियों के सुधार के लिए या उनकी उचित खेती या सिंचाई के लिए कोई जल-निकास संकर्म आवश्यक है,

या किन्हीं भूमियों के लिए बाढ़ से या जल के अन्य संचय से या किसी नदी द्वारा कटाव से संरक्षण के लिए अपेक्षित है, तो राज्य सरकार ऐसे जल-निकास संकर्म के लिए एक स्कीम बनवाएगी और उसकी लागत के प्राक्कलन को और ऐसी लागत के उस अनुपात के, जो राज्य सरकार चुकाने की प्रस्थापना करती है विवरण को और उस स्कीम की बाबत जिन भूमियों को प्रभार्य बनाने की प्रस्थापना हो उनकी अनुसूची को प्रकाशित कराएगी।

58. ऐसी स्कीमों पर नियोजित व्यक्तियों की शक्ति—ऐसी स्कीमों बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति धारा 14 द्वारा नहर अधिकारियों को प्रदत्त किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

59. संकर्मों द्वारा फायदा पाने वाली भूमियों पर दर—ऐसी स्कीम की बाबत, उन सभी भूमियों के स्वामियों पर जो, ऐसे नियमों द्वारा विहित रीति में, इस प्रकार प्रभार्य अवधारित किए जाएं, एक वार्षिक दर राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार, प्रभारित की जा सकती है।

ऐसी दर जहां तक हो सके इस प्रकार नियत की जाएगी कि निम्नलिखित परिसीमाओं में से किसी से भी अधिक न हो :—

(1) उक्त संकर्मों की प्रथम लागत पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष, उसमें उसके अनुरक्षण और अधीक्षण की प्राक्कलित वार्षिक लागत जोड़कर और उसमें से उक्त दर को अपवर्जित करते हुए संकर्म से होने वाली प्राक्कलित आय, यदि कोई हो, घटाकर;

(2) कृषि भूमि की दशा में; वह राशि जो भू-राजस्व के निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, ऐसी भूमि पर जल-निकास संकर्म द्वारा उसके वार्षिक मूल्य या उसके उत्पाद में हुई वृद्धि के कारण निर्धारित की जाए।

ऐसी दर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकतम के अन्तर्गत, परिवर्तित की जा सकती है।

जहां कोई त्रुटि जिसको ठीक किया जाना है किसी जलसरणी, मार्ग या अन्य संकर्म या बाधा के कारण, जो राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या कारित की गई है, वहां उक्त त्रुटि को ठीक करने के लिए अपेक्षित जल-निकास संकर्म की लागत का आनुपातिक हिस्सा, यथास्थिति, ऐसी सरकार या ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

60. दर की वसूली—ऐसी जल-निकास दर धारा 45, 46 और 47 में जल दरों के संग्रह और वसूली के लिए उपबन्धित रीति में संगृहीत और वसूल की जा सकती है।

61. प्रतिकर के दावों का निपटारा जाना—जब कभी धारा 55 के अधीन दी गई अधिसूचना के अनुसरण में कोई बाधा हटाई जाती है या उपान्तरित की जाती है,

या, जब कभी धारा 57 के अधीन जल-निकास संकर्म किया जाता है,

वहां उक्त बाधा के हटाने या उपान्तरित करने के या ऐसे संकर्म के निर्माण के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि के कारण प्रतिकर के सभी दावे कलक्टर के समक्ष किए जा सकेंगे और वह उनको धारा 10 में उपबन्धित रीति में निपटाएगा।

62. ऐसे दावों की परिसीमा—ऐसा कोई दावा परिवादित हानि के होने से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि कलक्टर का यह समाधान नहीं हो जाता है कि दावेदार को उक्त कालावधि के अन्दर दावा न करने का पर्याप्त कारण था।

भाग 8

नहरों और जल-निकास संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करना

63. “श्रमिक” की परिभाषा—इस भाग में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, “श्रमिक” शब्द के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट कोई हस्तशिल्प करते हैं।

64. नहर द्वारा फायदा पाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या विहित करने की शक्ति—किसी भी जिले में जिसमें कोई नहर या जल-निकास संकर्म राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या परियोजित किया जाता है, राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो, कलक्टर को निदेश दे सकती है कि—

(क) उन स्वत्वधारियों, उपस्वत्वधारियों या कृषकों को अभिनिश्चित करे जिनके ग्राम या जिनकी सम्पदा, कलक्टर के निर्णय में ऐसी नहर या जल-निकास संकर्म द्वारा फायदा पाएंगी, और

(ख) जिले की और उन सभी स्वत्वधारियों, उपस्वत्वधारियों या कृषकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सूची में, श्रमिकों की वह संख्या अभिलिखित करे जो उक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः ऐसे किसी ग्राम या सम्पदा से, ऐसी किसी नहर या निकास संकर्म पर नियोजन के लिए जब इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में अपेक्षा की जाए तब, दी जाएगी।

कलक्टर, समय-समय पर, ऐसी सूची या उसके किसी भाग में परिवर्द्धन या परिवर्तन कर सकता है।

65. अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करने की प्रक्रिया—जब कभी राज्य सरकार द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी नहर खण्ड अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यदि कोई संकर्म तुरन्त निष्पादित नहीं किया जाएगा, तो किसी नहर या जल-निकास संकर्म को ऐसी गम्भीर क्षति हो जाएगी, जिससे एकाएक और विस्तृत सार्वजनिक क्षति होगी,

और उसके उचित निष्पादन के लिए आवश्यक श्रमिक सामान्य रीति से उस समय के अन्दर, जो ऐसी क्षति को रोकने के लिए ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं तो, उक्त अधिकारी ऐसी सूची में नामित किसी व्यक्ति से उतने श्रमिक देने की अपेक्षा कर सकता है (जो उस संख्या से अधिक नहीं होंगे जिन्हें प्रदान करने का वह सूची के अनुसार दायी है) जो ऐसे संकर्म के तुरन्त निष्पादन के लिए उक्त अधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

इस प्रकार की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा लिखित होगी और उसमें निम्नलिखित का कथन होगा :—

(क) किए जाने वाले संकर्म की प्रकृति और स्थान;

(ख) जिस व्यक्ति से अध्यपेक्षा की गई है उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या; और

(ग) अनुमानित समय जिसके लिए और वह दिन जब श्रमिकों की आवश्यकता होगी,

और उसकी एक प्रति राज्य सरकार की सूचना के लिए नहर अधीक्षक अधिकारी को तुरन्त भेजी जाएगी।

राज्य सरकार, ऐसे किसी श्रमिक को संदाय की जाने वाली दर नियत करेगी, और समय-समय पर उसमें परिवर्तन कर सकती है :

परन्तु ऐसी दरें इसी प्रकार के काम के लिए आसपास में उस समय दी जाने वाली अधिकतम दरों से अधिक होगी।

ऐसे प्रत्येक श्रमिक की दशा में संदाय उस पूरी कालावधि में होता रहेगा जिसके दौरान, इस भाग के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, उसे अपनी सामान्य उपजीविका चलाने से रोका जाता है।

राज्य सरकार ¹*** यह निदेश दे सकती है कि इस भाग के उपबन्ध आवश्यक वार्षिक साफ सफाई करने के, या किसी नहर या जल निकास संकर्म के उचित रूप से चालू रहने में रुकावट या उसके साथ उतना हस्तक्षेप किए जाने को जिससे सिंचाई या जल निकास की स्थापित सरणी में रुकावट पड़े, निवारित करने के प्रयोजन के लिए किसी जिले या जिले के भाग को (यथास्थिति) या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से लागू होंगे।

66. अध्यपेक्षा के अधीन श्रमिकों का दायित्व—जब उक्त सूची में नामित किसी व्यक्ति से कोई अध्यपेक्षा की गई है तब, ऐसे व्यक्ति के ग्राम या संपदा के अन्दर सामान्यतः निवासी प्रत्येक श्रमिक उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अपना श्रम प्रदाय करने और करते रहने का दायी होगा।

भाग 9

अधिकारिता

67. इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता—जैसा कि इसमें अथवा उपबन्धित किया गया हो उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात की बाबत राज्य सरकार के विरुद्ध सभी दावों का सिविल न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सकेगा; किन्तु किसी भी मामले में ऐसा कोई न्यायालय ऐसे आदेश के समय बोर्डे गई या उगती हुई किसी फसल को नहरी जल प्रदाय करने के बारे में कोई आदेश नहीं करेगा।

68. जलसरणी में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में मतभेदों का निपटारा—जब कभी दो या अधिक व्यक्तियों की बीच किसी जलसरणी के उपयोग, निर्माण या अनुरक्षण की बाबत पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों के बारे में मतभेद होता है तब, ऐसा कोई व्यक्ति विवादग्रस्त मामले का कथन करते हुए नहर खण्ड अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकता है। तब ऐसा अधिकारी अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि ऐसी सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन वह उक्त मामले की जांच प्रारम्भ करेगा और, ऐसी जांच के पश्चात्, वह उस पर आदेश पारित करेगा, यदि वह कलक्टर को वह मामला अन्तरित न कर दे (जिसे करने के लिए एतद्द्वारा सशक्त किया जाता है), अन्तरित कर देने पर कलक्टर उक्त मामले में जांच करेगा और अपना आदेश पारित करेगा।

ऐसा आदेश ऐसे आदेश के किए जाने के समय बोर्डे गई या उगती हुई फसलों के लिए जल के उपयोग या वितरण के बारे में अन्तिम होगा, और सिविल न्यायालय की डिक्री द्वारा अपास्त किए जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

69. साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन जांच करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने से सम्बद्ध ऐसी सिविल शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता² द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदत्त की गई है; और ऐसी प्रत्येक जांच न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

भाग 10

अपराध और शास्तियां

70. अधिनियम के अधीन अपराध—कोई, जो बिना उचित प्राधिकार के और स्वेच्छा से निम्नलिखित कार्यों में से कोई करेगा, अर्थात् :—

- (1) किसी नहर या जल-निकास संकर्म को क्षति पहुंचाएगा, परिवर्तित करेगा, बढ़ाएगा या बाधा पहुंचाएगा;
- (2) किसी नहर या जल-निकास संकर्म में जल के प्रदाय में या उससे या उससे होकर या उस पर या उसके नीचे के जल के प्रवाह में हस्तक्षेप करेगा, वृद्धि करेगा या उसे घटाएगा;
- (3) किसी नदी या सरिता में जल के प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप या परिवर्तन करेगा कि कोई नहर या जल-निकास संकर्म संकटापन्न हो जाए या उसको नुकसान हो जाए या वह कम उपयोगी हो जाए;
- (4) किसी जलसरणी के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हुए, या जलसरणी का उपयोग करते हुए, उससे जल के दुर्व्यय को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा या उससे जल के प्राधिकृत वितरण में हस्ताक्षेप करेगा, या ऐसे जल का अप्राधिकृत रीति में उपयोग करेगा;
- (5) किसी नहर के जल को भ्रष्ट या कलुषित करेगा जिससे कि वह जिन प्रयोजनों के लिए सामान्यतया उपयोग किया जाता है उनके लिए कम उपयुक्त हो जाए;
- (6) राज्य सरकार द्वारा किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के प्रतिकूल किसी जलयान का किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन कराएगा;

¹ 1914 के अधिनियम सं० 4 द्वारा "सपरिपद गर्वनर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित किए गए।

² अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए।

(7) किसी नहर में नौपरिवहन करते समय, नहर की या उसमें के जलयानों की सुरक्षा के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा;

(8) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन श्रमिक देने का दायी होते हुए, उचित कारणों के बिना, उससे अपेक्षित श्रमिकों का प्रदाय करने में या प्रदाय करने में सहायता करने में असफल रहेगा;

(9) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन अपने श्रम का प्रदाय करने का दायी होते हुए, उचित कारण के बिना, अपना श्रम प्रदाय करने की और प्रदाय करते रहने की उपेक्षा करेगा;

(10) किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी तल चिह्न या तल गेज को नष्ट करेगा या हटाएगा;

(11) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल, ऐसा न करने की अपेक्षा किए जाने के पश्चात्, किसी नहर के संकर्म, तट या वाहिका या जल-निकास संकर्म पर से या पर होकर जानवर या यान चलवाएगा या चलवाएगा;

(12) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का जिसके भंग के लिए शास्ति उपगत हो सकती है;

शास्ति—वह ऐसे वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष जो राज्य सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का जो पचास रूप से अधिक नहीं होगा, या कारावास का जो एक मास से अधिक नहीं होगा, या दोनों का, भागी होगा।

71. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से निवारित नहीं करेगी;

परन्तु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

72. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर—जब कभी किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए जुर्माना किया जाता है तो, मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसा जुर्माना पूर्णतया या उसका भाग ऐसे अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में संदाय किया जाए।

73. बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति—किसी हरन या जल-निकास संकर्म का भारसाधक व्यक्ति या उस पर नियोजित व्यक्ति उसकी दृष्टि में निम्नलिखित अपराधों में से किसी को करने वाले व्यक्ति को ऐसी नहर या संकर्म की भूमि या भवनों से हटा सकता है या बिना वारण्ट के अभिरक्षा में लेकर तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन को, विधि के अनुसार व्यवहार किए जाने के लिए ले जा सकता है :—

(1) किसी नहर या जल-निकास संकर्म को जानबूझकर नुकसान या बाधा पहुंचाता है;

(2) बिना उचित प्राधिकार के किसी नहर या जल-निकास संकर्म में या से, या किसी नदी या सरिता में जल के प्रदाय या प्रवाह से इस प्रकार हस्तक्षेप करता है कि कोई नहर या जल-निकास संकर्म को नुकसान हो जाए या वह संकटापन्न या कम उपयोगी हो जाए।

74. “नहर” की परिभाषा—इस भाग में, “नहर” शब्द के अन्तर्गत (जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो) नहरों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अधिभोग की सभी भूमियां और ऐसी भूमियों पर राज्य सरकार के स्वामित्व या अधिभोग के सभी भवन, मशीनरी, बाड़, फाटक और अन्य परिनिर्माण, वृक्ष, फसल, बागान या अन्य उत्पाद हैं, ऐसा समझा जाएगा।

भाग 11

समनुषंगी नियम

75. नियम बनाने, परिवर्तित करने और रद्द करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है :—

(1) किसी अधिकारी की, जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी विषय में कार्यवाही करने की अपेक्षा है या जो इस निमित्त सशक्त किया गया है, कार्यवाहियां;

(2) वे मामले जिनमें, और वे अधिकारी जिनको, और वे शर्तें जिनके अधीन, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिए गए आदेश और विनिश्चय से, जिसकी अपील के बारे में अभिव्यक्ततः उपबन्ध नहीं किया गया है, अपील की जा सकेगी;

(3) वे व्यक्ति जिनके द्वारा [और] वह समय, स्थान या रीति जिससे कोई बात जिसके लिए जाने के लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, की जाएगी;

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी प्रभार की रकम;

¹ 1920 के अधिनियम सं० 38 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन” शब्द निरसित किए गए।

² 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा अंतःस्थापित।

(5) और साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए, राज्य सरकार, समय-समय पर ^{1***} इस प्रकार बनाए गए नियमों को परिवर्तित या रद्द कर सकती हैं।

नियमों का प्रकाशन—ऐसे नियम, परिवर्तन और रद्दकरण राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तब विधि का बल रखेंगे।

अनुसूची—[निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित।]

¹ 1920 के अधिनियम सं० 38 द्वारा “ऐसे ही नियंत्रणाधीन” शब्द निरसित किए गए।